



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 167]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18, 1982/भाद्र 27, 1904

No. 167] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18, 1982/BHADRA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 46-आई०टी०सी० (पी०एन०)/82

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1982

विषय:—अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं और बहुपक्षीय या द्विपक्षीय विदेशी सहायता द्वारा वित्तदान की गई परियोजनाओं के मद्दे भारत में की गई आपूर्तियां सीमा शुल्क से आयातित निवेश के लिये छूट।

मिसिल सं० 1/45/आर०ई०पी०/74-ई०पी० सी० (5). —वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 16-आई टी सी (पी एन) /82 दिनांक 5 अप्रैल, 1982 के अधीन प्रकाशित आयात एवं निर्यात नीति, 1982-83 (जिल्द-1) की कंडिका 131(ख) तथा (च) में यथा निर्धारित आयात प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं और बहुपक्षीय या द्विपक्षीय विदेशी सहायता द्वारा वित्तदान की गई परियोजनाओं के मद्दे भारत में की गई आपूर्तियां "किये गये निर्यातों" के रूप में समझी जाती है।

2. वित्त मंत्रालय ने 10 सितम्बर, 1982 को एक अधिसूचना जारी की है जिसकी एक प्रति प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के साथ लगाई जाती है जो उपर्युक्त कंडिका 1 में उल्लिखित संविदाओं के मद्दे संभरण किये जाने वाले माल के विनिर्माण के लिये अपेक्षित कच्चे माल और सफटको के आयात के लिये सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है। परन्तु यह वित्त-मंत्रालय की उक्त अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

3. वित्त मंत्रालय की उपर्युक्त अधिसूचना के अधीन जो विनिर्माता निर्यातक कर छूट का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें विशेष अध्याय आयात लाइसेंस/रिहाई आदेश जारी किये जायेंगे। ऐसे लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र आर ई पी लाइसेंसों के जारी होने के साथ संबद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को बिल्कुल उसी विधि से और तरीके से किये जाने चाहिये जैसा कि कर छूट योजना के अधीन अधिम लाइसेंसों के लिये आवेदन करने के लिये निर्धारित किया गया है। आवेदन पत्र 1982-83 के लिये आयात नीति के परिशिष्ट 19 के अनुबन्ध-2 में दर्शाये गये प्रपत्र में किये जा सकते हैं और इनके साथ यथा निर्धारित प्रपत्र में सनदी अभियंता का एक प्रमाण-पत्र भेजा जाना चाहिये। आवेदन पत्र संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिये और उसकी प्रतियां (1) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (ई पी-2 अनुभाग) नई दिल्ली, (2) महानिदेशक, तकनीकी विकास (आयात तथा निर्यात नीति सेल), नई दिल्ली और (3) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) मार्ग ब्लाक, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिये।

4. आवेदन-पत्रों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय में निर्यात आयुक्त को अध्यक्षता में गठित एक समिति "विशेष अध्याय लाइसेंस समिति" (एस आई एस सी) द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जायेगा। संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र पर भागामी कार्यवाही समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन को ध्यान में रखकर की जायेगी। समिति को यह अधिकार होगा कि वह विचार के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र को मामले की पात्रता के आधार पर रद्द कर दें।

5. जारी किये गये आयात लाइसेंसों/रिहाई आदेशों पर उपर्युक्त कंडिका 1 में यथा उल्लिखित संभरण के लिये संविदाओं के अनुसार संबद्ध परियोजना प्राधिकारी को माल के संभरण के लिये एक उपयुक्त आधार का पृष्ठांकन किया जायेगा और ऐसी शर्तें पृष्ठांकित की जायेंगी

जा आवश्यक समझा जाये। लाइसेंस/रिटर्न आदेश के धारक के लिये भी यह आवश्यक होगा कि वह निर्धारित किये जाने वाले प्रपत्र और विधि के अनुसार आभार का पूरा करने के लिये एक उपयुक्त बांड निष्पादित करे।

6 आभार बांड का नवी रिहा किया जायेगा जबकि लाइसेंस/रिटर्न आदेश के धारक ने निर्धारित अवधि के भीतर आभार पूरा करने के लिये लाइसेंस प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिये दस्तावेजों साध्य प्रस्तुत कर दिया हो। लाइसेंस प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आभार को पूरा करने में परियोजना प्राधिकारी का संभरण किये गये माल का स्वयं जाकर सत्यापन करे। इसे नोट कर लिया जाये कि आभार को पूरा करने के लिये कबल वे ही माल पाव होंगे जा जैसा भी मामला हो, विशेष प्रस्ताव तदनुसार के मदे सीमा शुल्क के माध्यम से आयातित कच्चे माल और मण्डको की निकासी के बाद संभरित किये जाते हैं या मरणी-खंड ध्वस्त वाले अतिवर्ण से रिहाई आदेश के मदे संभरण प्राप्त करने के बाद स रित किये जाते हैं।

7 किसी कारण से जिस मामले में आभार में निर्धारित सीमा तक जितने ऐसी निर्धारित अवधि भी शामिल है जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई है माल की पूर्ति नहीं की जाती है तो, संबंधित विनिर्माता सम्भरित न किये गये उत्पादों के अनुरूप कर छूट प्राप्त माल की आनुपातिक मात्रा का सीमा शुल्क कर भुगतान करेगा। वह ऐसे फालतु माल के लिये भी सीमा शुल्क कर का भुगतान करेगा जो परिणामी उत्पादों का उपयोग करने और आभार को पूरा करने के बाद छूट गया हो। इसके अतिरिक्त वह आयातित माल की निकासी की तारीख से उस तारीख तक ऐसी देय कुल धनराशि पर 18% की दर में व्याज का भुगतान करेगा। जिस तारीख को उसने देय धनराशि का वास्तव में भुगतान किया है। सीमा शुल्क कर की धनराशि और उसके व्याज से सगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत सीमा शुल्क के लेख में डाला जायेगा। निर्यात आभार पूरा करने में असमर्थ रहने पर आयात नियंत्रण कानून और/या बांड की शर्तों के अन्तर्गत की जाने वाली किसी भी अन्य कार्यवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रावधान लागू होंगे।

8 छ महीने तक आभार को पूरा करने के लिये अवधि में वृद्धि प्रदान करने के लिये आवेदनो पर संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है। इससे आगे की समय वृद्धि के लिये उपर्युक्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

9. आभार को पूरा करने के बाद विनिर्माता निर्यातक खुले सामान्य लाइसेंस की मध्य के मूल्य या आयात नीति के परिशिष्ट 5 और 7 में प्रवर्णित मदों के मूल्य या पैकिंग सामग्री के मूल्य को लेख में लिये बिना ही, यदि कोई हों तो शेष मूल्य के लिये आयात नीति 1982-83 के परिशिष्ट 17 के अनुसार यथा अनुमेय आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिये पात्र होंगे।

मणि नागायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

सार्वजनिक सूचना

सं० 46-आई टी सी (पी एन)/82

दिनांक 18 सितम्बर, 1982 का अनुबन्ध

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1982

अधिसूचना

सं० 210/82 कस्टम्स

जी०एच०आर०, 360 (ई)--सीमाशुल्क अधिनियम, 1982 (1982 का 52) के खंड 25 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होने हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक

हित में आवश्यक है, केंद्रीय सरकार एतद्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध या अन्तर्राष्ट्रीय पुन निर्माण और विकास बैंक या द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं का स रित किये जाने वाले माल के निर्माण के लिये अशेषित कच्ची सामग्री और मण्डको को इनका भाग में आयात होने पर इन पर उगाहे जाने वाले पूर्ण सीमाशुल्क जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में वर्णित गया है, से और उपर्युक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के खंड 3 के अन्तर्गत उन कच्ची सामग्री और मण्डको पर उगाहे जाने वाले पूर्ण अतिवर्ण से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है, अर्थात् --

- (1) यह कि आयातक को पूर्वोक्त उद्देश्य के लिये कच्ची सामग्री और मण्डको के आयात या रिहाई के लिये आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में यथा निर्दिष्ट लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा सम्बद्ध मरणीबद्ध एंजरी के लिये आवश्यक आयात लाइसेंस या रिहाई आदेश प्रदान किया गया हो,
- (2) यह कि आयात लाइसेंस में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न-लिखित पृष्ठांकन समाविष्ट हो --
 - (क) उक्त लाइसेंस के अधीन आयात के लिए अनुमति कच्ची सामग्री और मण्डको का विवरण, मात्रा और मूल्य
 - (ख) कर-मुक्त आयात के लिये अनुमित कच्ची सामग्री का विवरण और मात्रा, और
 - (ग) आयातित सामग्री से या उसके साथ निर्माण किये जाने वाले माल का विवरण और मात्रा।
- (3) यह कि आयातक ने इस अधिसूचना में निर्धारित आभारों और शर्तों को पूर्ण करने के लिये और उक्त लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यह सिद्ध करने पर कि उक्त कच्ची सामग्री और मण्डको का पूर्वोक्त उद्देश्य के लिये उपयोग नहीं हुआ है, उस कच्ची सामग्री और मण्डको पर उगाहा जाने वाले धनराशि के बराबर धन राशि की मांग होने पर चुकाने के लिये स्वयं को बाध्य करने हुए उक्त लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित धनराशि और प्रपत्र में एक बांड का निष्पादन किया हो, और
- (4) यह कि आयातक ने उक्त लाइसेंस प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिये सीमाशुल्क के संबंध में अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिये और उक्त लाइसेंस के प्रति अपने-अपने आभारों को पूर्ण करने के लिये साध्य प्रस्तुत किया हो।

2. यह अधिसूचना 10 सितम्बर, 1982 तक इस दिन को शामिल करते हुए लागू रहेगी।

[मि० सं० 355/67/82-कस्टम्स]
जैड०वी० नागरकर, ध्वज सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 46-ITC(PN)/82

New Delhi, the 18th September, 1982

Subject—Supplies made in India against IBRD/IDA aided projects and projects financed by multilateral or bilateral external assistance—exemption of imported inputs from customs duty

File No 1/45/Rep./74-EPC(V).—Supplies made in India against IBRD/IDA aided projects and projects financed by

multilateral or bilateral external assistance, are treated as "deemed exports" for the purpose of import replenishment, as laid down in para 131(b) and (f) of Import & Export Policy, 1982-83 (Vol I), published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 16-ITC(PN)/82 dated the 5th April, 1982.

2. The Ministry of Finance have issued a notification, dated 10th September, 1982, a copy of which is annexed to this Public Notice, which exempts from payment of customs duty, the import of raw materials and components required for the manufacture of goods to be supplied against contracts referred to in para 1 above, subject to the conditions laid down in the said notification of the Ministry of Finance.

3. Special Imprest import licences/release orders will be issued to manufacturer-exporters intending to take advantage of the duty exemption under the said notification of the Ministry of Finance. Applications for such licences should be made to the regional licensing authorities concerned with the issue of REP licences, in the same form and manner as laid down for making applications for Advance licences under the Duty Exemption Scheme. The applications may be made in the form given in Annexure II of Appendix 19 of import policy, 1982-83 accompanied by a certificate of the chartered engineer in the prescribed form as laid down. The application should be made to the licensing authority concerned, with copies thereof to (i) Chief Controller of Imports & Exports (E.P. II Section), New Delhi, (ii) DGTD (Import & Export Policy Cell) New Delhi, and (iii) Ministry of Finance (Department of Revenue), North Block, New Delhi.

4. The applications will be considered on merits by a Committee set-up under the Export Commissioner in the Office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, called "Special Imprest Licensing Committee" (SILC). Further action on the application will be taken by the licensing authority concerned keeping in view the approval given by the Committee. It will be open to the Committee to reject approval of an application placed before it for consideration, depending on the merits of the case.

5. The import licences/Release Orders issued will bear a suitable obligation for the supply of goods to the concerned project authority in accordance with the contracts for supply as referred to in para 1 above, and such other conditions as may be considered necessary. The licence/Release Order holder will also be required to execute a suitable bond for discharge of the obligation in the form and manner as may be laid down.

6. The obligation bond will be discharged after the licence/Release Order holder has produced documentary evidence to the satisfaction of the licensing authority for the discharge of the obligation within the stipulated period. It will be open to the licensing authority to carry-out physical verification of the goods supplied to the project authority in discharge of the obligation. It may be noted that only those goods will qualify for the discharge of the obligation as are supplied after the date of clearance of imported raw materials and components through the customs against the special Imprest licence or after obtaining supplies against Release Order from the canalising agency, as the case may.

7. Where for any reason, supplies of goods to the extent specified in the obligation are not made within the stipulated period including the extensions, if any, granted by the licensing authority, the manufacturer concerned shall pay Customs duty on the proportionate quantity of exempt material corresponding to the products not supplied. He shall also pay the customs duty on any excess material that has been left over after utilisation in the resultant products and completion of the obligation. He shall, in addition, pay interest at 18 per cent on the total amount thus payable, from the date of clearance of imported goods to the date on which the amount due from him is actually paid. The amount of customs duty and the interest thereon shall be credited to the Customs Account under the relevant Head of Account. These provisions will be without prejudice to any other action that may be taken under the import control law and/or in

terms of the bond, for failure to discharge the export obligation.

8. Requests for extension in the period for the discharge of obligation upto six months may be considered by the licensing authority concerned. Further extensions will be considered by the aforesaid Committee.

9. The manufacturer-exporters after fulfilling the obligation will be eligible to import replenishment licence, as admissible in terms of Appendix 17 of import policy, 1982-83, for the balance value, if any, without taking into account the value of OGL items or items appearing in Appendices 5 and 7 of import policy, or packing materials.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller
Import and Export.

ANNEXURE TO PUBLIC NOTICE NO. 46-ITC(PN)/82,
DATED THE 18TH SEPTEMBER, 1982

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 1982

No. 210/82-CUSTOMS

G.S.R. 560(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts raw materials and components required for the manufacture of goods to be supplied to International Development Association or International Bank for Reconstruction and Development or Bilateral or Multilateral aided projects, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable therein, which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act subject to the following conditions, namely :—

- (1) that the importer has been granted necessary import licence or release order on the concerned canalising agency by the licensing authority as specified in the Import (Control) Order, 1955, for the import or release of raw materials and components for the aforesaid purpose ;
- (2) that the import licence contains the following endorsements inter-alia :—
 - (a) the description, quantity and value of raw materials and components allowed to be imported under the said licence ;
 - (b) the description and quantity of raw materials and components allowed to be imported duty-free ;
 - (c) the description and quantity of goods to be manufactured out of or with, the imported materials ;
- (3) that the importer executes a bond in such form for such sum as may be specified by the said licensing authority binding himself to fulfill the conditions and conditions stipulated in this notification and to pay on demand, an amount equal to the duty leviable on the said raw materials and components as are not proved to the satisfaction of the said licensing authority to have been used for the aforesaid purpose ; and
- (4) that the importer produces evidence to the satisfaction of the said licensing authority, for the purpose of discharging the liability respect of duty as well as for discharging the obligation against the said licence.

2. This notification shall be in force upto and to the 10th day of September, 1987.

[F. No. 333/67/
Z. B. NAGARKAR, U]

